



मरुस्थल में एशिया की सबसे बड़ी डेजर्ट आर्टिफिशियल झील तैयार

50 लाख आबादी को 365 दिन मिलेगा पानी

नहरबंदी का संकट हमेशा के लिए खत्म, जुलाई में सीएम करेंगे उद्घाटन

28 किलोमीटर लंबी और 33 फीट गहरी झील में रहेगा 141 करोड़ लीटर पानी का बैंकअप

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में पानी की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में जलदाय विभाग ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। थार के रेगिस्तान में 28 किलोमीटर लंबी और 33 फीट (10 मीटर) गहरी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित रेगिस्तानी झील (मेगा वाटर स्टोरेज जलाशय) बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है। करीब 242 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ यह विशालकाय 'वाटर बैंक' जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की लगभग 50 लाख आबादी के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। जलदाय विभाग का दावा है कि इस जिगजैग झील से 365 दिन पानी सप्लाई की जा सकेगी। दावा है कि इस झील को पार (एक से दूसरे छोर) करने में करीब 24 घंटे का समय लगेगा। रेगिस्तानी मिट्टी इसमें भरा पानी न सोख ले, इसके लिए इसमें नीचे 300 माइक्रोन की स्पेशल प्लास्टिक शीट बिछाई गई है जो पानी को जमीन में जाने से रोकेंगी। इसमें इंदिरा गांधी नहर से आया बारिश का पानी स्टोर किया जाएगा, इसके बाद फिल्टर प्लांट से बाड़मेर-जैसलमेर के घरों में पहुंचाया जाएगा। इससे 50 लाख की आबादी को एक साल तक लगातार पानी दिया जा सकेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे।

इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना : पानी सोखने नहीं, बिछेगी स्पेशल प्लास्टिक शीट -



रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह पानी को बहुत तेजी से सोख लेती है। यदि इस झील में सीधा पानी भरा जाता, तो करोड़ों लीटर पानी जमीन के नीचे रिसकर गायब हो जाता। इस प्राकृतिक बाधा को दूर करने के लिए इंजीनियरों ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। पूरी झील के निचले हिस्से (71 लाख स्क्वायर मीटर बेस एरिया) में हाई डेंसिटी पॉलिथिलीन प्लास्टिक शीट बिछाई गई है जो पानी के रिसाव (सीपेज) को 100% रोकती है। प्लास्टिक लेयर को फटने या खराब होने से बचाने के लिए इसके ऊपर ढाई फीट (80 सेंटीमीटर) मोटी मिट्टी की सुरक्षात्मक परत डाली गई है। अधिकारियों का दावा है कि यह सिस्टम अगले 100 वर्षों तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। झील के घुमावदार (जिगजैग) किनारों को सीमेंट और कंक्रीट से पक्का किया गया है।

ऐसे पहुंचेगा घरों तक शुद्ध पानी -



झील में पानी एकत्रित होने के बाद इसे बड़े-बड़े हाई-प्रेसर पाइपों के माध्यम से मोहनगढ़ फिल्टर प्लांट भेजा जाएगा। वहां पानी को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से पूरी तरह फिल्टर और शुद्ध (प्युरिफाई) किया जाएगा। इसके बाद मुख्य पाइपलाइनों के जरिए जैसलमेर और बाड़मेर के शहरी व सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के घरों तक 365 दिन निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

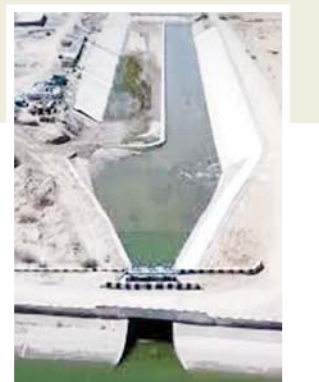
जल सुरक्षा के लिए 'गेम-चेंजर'

इस विशालकाय जलाशय के आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति इस झील के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चक्कर लगाना चाहे, तो उसे लगभग 24 घंटे का समय लग जाएगा। आज के दौर में जब पानी की एक-एक बूंद अमूल्य है, थार के सीने पर बना यह 'जल समंदर' मरुभूमि के भविष्य की जल सुरक्षा के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने जा रहा है।



अब नहरबंदी में भी नहीं रुकेगी सप्लाई, 141 करोड़ लीटर का बैंकअप -

हर साल इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत और सफाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान को करीब एक महीने तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता था। जलदाय विभाग के सूत्रों के अनुसार इस नवनिर्मित जलाशय की कुल भंडारण क्षमता 1413 मिलियन क्यूबिक फीट (लगभग 141 करोड़ लीटर) है। इसमें सालभर का पानी सुरक्षित रखने का बैंकअप रहेगा। मानसून के दौरान जब पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होती है, तब इंदिरा गांधी नहर में आने वाले अतिरिक्त (सरप्लस) पानी को 1 किलोमीटर लंबे एस्केप चैनल और दो बड़े गेट्स के जरिए इस झील में डाइवर्ट कर स्टोर किया जाएगा।



दिल्ली में काँकरोच जनता पार्टी का 5 घंटे प्रदर्शन

अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा; अगले शनिवार फिर जंतर-मंतर पर जुटने का ऐलान

नई दिल्ली

NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काँकरोच जनता पार्टी, यानी CJP ने शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। पार्टी के फ़ाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा था कि मंत्री आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा दें, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। अगले शनिवार, यानी 13 जून को जंतर-मंतर पर फिर प्रदर्शन



करेंगे। CJI को जंतर-मंतर पर आज शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी, लेकिन दोपहर 3:30 बजे अभिजीत की तबीयत खराब हो जाने के बाद यह समाप्त हो गया। इसके बाद में सोनम वांगचुक के साथ धरनास्थल से रवाना हो गए।

अभिजीत सुबह ही अमेरिका से दिल्ली लौटे थे। वे एयरपोर्ट से सीधे जंतर-मंतर पहुंचे थे। यहां अभिजीत अंबेडकर की आँटी बायोग्राफी और संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे थे।

प्रदर्शन शामिल हुए सोनम वांगचुक

प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, CPI(ML) लिबरेशन के महासचिव दिपांकर भट्टाचार्य, CPI नेता एनी राजा और वामपंथी छात्र और युवा संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

वैष्णो देवी जा रही ट्रेन में हादसा: लुधियाना में 2 हिस्सों में बंटी

लुधियाना

ट्रेन के स्लीपर कोच में यह हादसा हुआ। मोशन ग्राफिक में देखें। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर वैष्णो देवी जा रही 1200 यात्रियों से भरी ट्रेन में हादसा हो गया। यहां ट्रेन के स्लीपर कोच का टॉयलेट अचानक धमाके जैसी आवाज के साथ टूट गया। जिसके बाद यह कोच अपने साथ वाले डिब्बे से अलग हो गया। धमाके जैसी आवाज सुनते ही यात्रियों में अफ़रातफ़री मच गई। वह डिब्बे से बाहर आ गए। खुशकिस्मती की बात ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ, ट्रेन लुधियाना से चली ही थी। अगर हाईस्पीड के दौरान यह हादसा होता तो यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था। न्यू दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल (04081) नाम की यह ट्रेन आज (शनिवार) तड़के ढाई बजे के बाद नई दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई। सुबह 8.47 बजे पर यह लुधियाना स्टेशन पर पहुंची।

होटल क्लार्क्स-आमेर को सीज करने की चेतावनी

लेबर कोर्ट ने कहा- 34 साल पहले हटाए कर्मचारी को पैसा दो वरना एवशन होगा

जयपुर

जयपुर की लेबर कोर्ट ने होटल क्लार्क्स आमेर को सीज करने की चेतावनी दी है। होटल के पूर्व कर्मचारी ने गलत तरीके से हटाने और 34 साल से बकाया नहीं देने के मामले की सुनवाई हुई। लेबर कोर्ट-1 के जज दिनेश गुप्ता ने होटल क्लार्क्स आमेर को 8 जून तक कर्मचारी को 6.25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करने के आदेश

दिए। जज दिनेश गुप्ता ने फैसला में कहा- याचिकाकर्ता कर्मचारी की मांगी गई 24.25 लाख की राशि की एक चौथाई रकम 6 लाख रुपए और हर्जाने की राशि के 25 हजार रुपए कर्मचारी के खाते में जमा करवाएं या उसके नाम का चेक-डीडी कोर्ट में पेश करें। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 जून को शाम 6 बजे तक आदेश की पालना नहीं करने पर उसी दिन कृर्की वारंट जारी कर तामील के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर को भिजवाया जाएगा। कृर्की वारंट पर होटल को सीज करके सुरक्षाकर्मी तैनात करने के आदेश दिए हैं।

सम्पादकीय

“मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो विस्तारस्वतंत्रता का हवन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार”

दिल्ली की आग: लपटों से नहीं, लापरवाही से जलता शहर



बार-बार दोहराता एक ही सच

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल आग लगने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। इन हादसों से बार-बार महानगर के बुनियादी ढांचे, विद्युत प्रणालियों और सुरक्षा नियमों में खामियां सामने आती हैं ताजा मामला दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में लगी भीषण आग का है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले विवेक विहार में लगी आग में नौ लोगों की जान चली गई थी। इस तरह की घटनाओं ने अवैध निर्माण, प्रशासनिक हिरासत और कानूनों की अवहेलना की बढ़ती परिपाटी के खतरनाक गठजोड़ को उजागर किया। अग्नि सुरक्षा तंत्र और प्रशासनिक ढांचा कागजों तक सीमित हैं। मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगी, वहां सरकार ने छह कमरों की इजाजत दी थी और 25 कमरे चलाए जा रहे थे। नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा था। सवाल यह है कि कानून एवं प्रवर्तन एजेंसियां क्या कर रही थीं? दिल्ली के शहरी विस्तार ने एक विरोधाभास पैदा कर दिया है। यहां प्रशासन विकेंद्रित है। कई एजेंसियों—दिल्ली दमकल सेवा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार आदि—के बीच कामकाज बंटा हुआ है। जब कोई हादसा होता है, तो एक विभाग दूसरे पर आरोप मढ़ कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। प्रशासनिक गतिरोध के कारण जवाबदेही शून्य हो जाती है। संकरी गलियां, अनधिकृत निर्माण, एक ही प्रवेश एवं निकास द्वार, और अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना काम चलाना आम बात है। सख्त कानूनों के बावजूद, जमीनी स्तर पर भवन निर्माताओं और अवैध संचालकों में नियमों के पालन का कोई डर नहीं है। कई इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जो अवैध होती हैं, उनमें अक्सर अग्नि सुरक्षा नियम का ध्यान नहीं रखा जाता। अग्नि सुरक्षा को दरकिनार किया जाना भी गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह के हादसे प्रशासनिक और नागरिक लापरवाही का जीता-जागता प्रमाण हैं। सवाल उठता है कि अनियोजित विस्तार की अंधी दौड़ में जान-माल से समझौता कब तक होता रहेगा? नगर निकायों से संबंधित नियम शहरी सुरक्षा की रीढ़ होते हैं। आपातकालीन निकास, विद्युत भार क्षमता, निर्धारित दूरी और अग्नि सुरक्षा मार्गों और भवन निर्माण से संबंधित मानदंड दशकों के अनुभव के आधार पर तैयार किए गए हैं। इनका उल्लंघन इमारतों को मौत के जाल में बदल देता है। सुविधा, प्रतिष्ठा या लाभ की लालसा में कानूनों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति हादसों को निम्नगण देती है। कायदे से नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन्हें ताक पर रखकर इमारत बनाने वालों और रिश्तत लेकर उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। नगर निकायों को नियमों के अनुपालन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना चाहिए। शहरी आवास के बदलते स्वरूप भी चिंताजनक हैं। शहर आधुनिक विलासिता तो चाहता है, लेकिन अक्सर सुरक्षित जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। एक आधुनिक शहर वह नहीं है, जिसमें ऊंची इमारतें, विलासिता, अनाप-शनाप कमाई हो, बल्कि वह है जहां मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

तंत्र और प्रशासनिक ढांचा कागजों तक सीमित हैं। मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगी, वहां सरकार ने छह कमरों की इजाजत दी थी और 25 कमरे चलाए जा रहे थे। नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा था। सवाल यह है कि कानून एवं प्रवर्तन एजेंसियां क्या कर रही थीं? दिल्ली के शहरी विस्तार ने एक विरोधाभास पैदा कर दिया है। यहां प्रशासन विकेंद्रित है। कई एजेंसियों—दिल्ली दमकल सेवा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार आदि—के बीच कामकाज बंटा हुआ है। जब कोई हादसा होता है, तो एक विभाग दूसरे पर आरोप मढ़ कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। प्रशासनिक गतिरोध के कारण जवाबदेही शून्य हो जाती है। संकरी गलियां, अनधिकृत निर्माण, एक ही प्रवेश एवं निकास द्वार, और अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना काम चलाना आम बात है। सख्त कानूनों के बावजूद, जमीनी स्तर पर भवन निर्माताओं और अवैध संचालकों में नियमों के पालन का कोई डर नहीं है। कई इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जो अवैध होती हैं, उनमें अक्सर अग्नि सुरक्षा नियम का ध्यान नहीं रखा जाता। अग्नि सुरक्षा को दरकिनार किया जाना भी गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह के हादसे प्रशासनिक और नागरिक लापरवाही का जीता-जागता प्रमाण हैं। सवाल उठता है कि अनियोजित विस्तार की अंधी दौड़ में जान-माल से समझौता कब तक होता रहेगा? नगर निकायों से संबंधित नियम शहरी सुरक्षा की रीढ़ होते हैं। आपातकालीन निकास, विद्युत भार क्षमता, निर्धारित दूरी और अग्नि सुरक्षा मार्गों और भवन निर्माण से संबंधित मानदंड दशकों के अनुभव के आधार पर तैयार किए गए हैं। इनका उल्लंघन इमारतों को मौत के जाल में बदल देता है। सुविधा, प्रतिष्ठा या लाभ की लालसा में कानूनों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति हादसों को निम्नगण देती है। कायदे से नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन्हें ताक पर रखकर इमारत बनाने वालों और रिश्तत लेकर उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। नगर निकायों को नियमों के अनुपालन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना चाहिए। शहरी आवास के बदलते स्वरूप भी चिंताजनक हैं। शहर आधुनिक विलासिता तो चाहता है, लेकिन अक्सर सुरक्षित जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। एक आधुनिक शहर वह नहीं है, जिसमें ऊंची इमारतें, विलासिता, अनाप-शनाप कमाई हो, बल्कि वह है जहां मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

रामगोपाल बिश्नोई

विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखते जलस्रोत और घटती जैव विविधता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और अधिक कठिन हो जाएगा। ऐसे समय में हमें यह समझना होगा कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है।

थार मरुस्थल के संदर्भ में यह चिंता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन-व्यवस्था की रीढ़ है। इसे मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है। अकाल और सूखे के समय इसकी सांगरी मनुष्य के भोजन का सहारा बनती है, इसकी पत्तियां पशुओं के लिए उत्तम चारा उपलब्ध कराती हैं और इसकी छाया भीषण गर्मी में जीवनदायिनी साबित होती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि खेजड़ी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, नमी बनाए रखने तथा मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि राजस्थान की संस्कृति, लोकजीवन और कृषि व्यवस्था में खेजड़ी का विशेष स्थान रहा है।

भारतीय संस्कृति और दर्शन भी प्रकृति को पूज्य मानते हैं। अथर्ववेद का उद्धरण — माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या: — अर्थात् पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, मनुष्य और प्रकृति के अटूट संबंध को दर्शाता है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति संरक्षण

पर्यावरण : संविधान का मूल्य, जीवन का आधार

- बाबूलाल नागा

हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानव समाज को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराने का अवसर है। जल, जंगल, जमीन, स्वच्छ वायु और जैव विविधता केवल एक सामाजिक या वैज्ञानिक विषय नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और नागरिक दायित्वों से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है।

भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल शासन व्यवस्था संचालित करना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जिसमें प्रत्येक नागरिक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सके। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और प्रदूषणमुक्त वातावरण के बिना जीवन के अधिकार की कल्पना अधूरी है। संविधान की इसी भावना को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 48(क) में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। वहीं अनुच्छेद 51(क)(ग) प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करे तथा जीव-जंतुओं के प्रति करुणा का भाव रखे। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व भी है। संविधान स्पष्ट संदेश देता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करना दरअसल जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा करना है। भारतीय न्यायपालिका ने भी पर्यावरण को जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त

विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष



को केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि धर्म माना था। यही परंपरा आगे चलकर बिश्नोई समाज के जीवन मूल्यों में दिखाई देती है, जहां वृक्षों और वन्यजीवों की रक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया गया।

खेजड़ी संरक्षण की बात आते ही 1730 का खेजड़ली बलिदान इतिहास के स्वर्णिम पलों में दर्ज दिखाई देता है। जब जोधपुर रियासत के सैनिकों ने खेजड़ी वृक्षों की कटाई शुरू की, तब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री-पुरुषों ने वृक्षों से चिपककर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन वृक्षों को बचाने के संकल्प से पीछे नहीं हटे। विश्व इतिहास में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया यह सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति भारतीय समाज की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

दुर्भाग्य से आज तीन सौ वर्ष बाद भी खेजड़ी सुरक्षित नहीं है। सड़क, उद्योग, खनन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़ी संख्या में

खेजड़ी वृक्षों का विनाश हो रहा है। हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के दौरान भी हजारों खेजड़ी वृक्ष प्रभावित हुए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा निश्चित रूप से समय की आवश्यकता है, लेकिन हरित ऊर्जा का अर्थ हरियाली का विनाश नहीं हो सकता। यदि स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर सदियों पुरानी पारिस्थितिकी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह विकास का टिकाऊ मॉडल नहीं कहा जा सकता।

इसी संदर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी खेजड़ी संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया कि क्या हरित ऊर्जा के नाम पर ऐसे वृक्षों की बलि दी जा सकती है जो सदियों से मरुस्थल के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए हुए हैं। न्यायालय की यह चिंता केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पिछले लगभग दो वर्षों से राजस्थान में खेजड़ी

जीवन के अधिकार में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है। यदि किसी व्यक्ति को स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और प्रदूषणमुक्त वातावरण उपलब्ध नहीं है, तो उसके मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। इस दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि मानव अधिकारों का भी विषय है।

वर्तमान समय में पर्यावरणीय संकट लगातार

डाल रही है। इसलिए आज आवश्यकता ऐसे विकास मॉडल की है जो आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करे। सतत विकास की अवधारणा इसी दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। विकास की प्रत्येक योजना में पर्यावरणीय प्रभावों का गंभीर मूल्यांकन होना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व इसी संदर्भ में और अधिक बढ़ जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल वर्तमान पीढ़ी की संपत्ति नहीं है। हम इसे अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उधार लेकर उपयोग कर रहे हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न केवल आज का नहीं, बल्कि भविष्य का भी है। यदि हम अभी से प्रकृति के प्रति जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को जल, वायु और खाद्य सुरक्षा जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल सरकारी नीतियां पर्याप्त नहीं हैं। जनभागीदारी और सामाजिक जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कम उपयोग, ऊर्जा की बचत, जैव विविधता की रक्षा और स्वच्छता जैसे छोटे-छोटे कदम भी बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। जब नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को समझते हुए पर्यावरण संरक्षण को जीवनशैली का हिस्सा बनाएंगे, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होगा। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यही संदेश देता है कि पर्यावरण केवल एक विषय नहीं, बल्कि संविधान का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। प्रकृति के संरक्षण में ही मानवता का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण संरक्षण को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि संवैधानिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करेंगे। यही एक स्वस्थ, सुरक्षित और समतामूलक भारत के निर्माण का मार्ग है तथा आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सच्ची जिम्मेदारी भी। (लेखक भारत अपडेट के संपादक हैं)



गंभीर होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल स्तर में गिरावट, वनों की कटाई और जैव विविधता का क्षरण पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कई क्षेत्रों में जल संकट गहरा रहा है, गर्मी के नए रिकार्ड बन रहे हैं और अनियमित वर्षा के कारण कृषि तथा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। आधुनिक विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो पर्यावरण को नष्ट कर दे, अंततः मानव समाज के लिए ही संकट पैदा करता है। बड़े उद्योग, खनन परियोजनाएं, शहरी विस्तार और उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव

संरक्षण के लिए व्यापक जनआंदोलन चल रहा है। पर्यावरण प्रेमी, किसान, सामाजिक संगठन और बिश्नोई समाज लगातार यह मांग कर रहे हैं कि खेजड़ी को विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए तथा इसके लिए एक प्रभावी खेजड़ी संरक्षण कानून बनाया जाए। आंदोलन का मूल उद्देश्य विकास कार्यों को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास और पर्यावरण साथ-साथ आगे बढ़ें। जब तक खेजड़ी जैसे जीवनदायी वृक्षों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक इनके संरक्षण की लड़ाई अधूरी रहेगी।

आज आवश्यकता केवल नए पौधे लगाने की नहीं, बल्कि उन परिपक्व वृक्षों को बचाने की है जो दशकों से पर्यावरण को संतुलित बनाए हुए हैं। एक विकसित खेजड़ी वृक्ष का पारिस्थितिक योगदान हजारों नए पौधों से अधिक होता है। इसलिए नीति निर्माण में वृक्ष संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए छतों, नहरों के ऊपर, बंजर एवं अनुपयोगी भूमि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि जैव विविधता और पारिस्थितिकी को न्यूनतम नुकसान पहुंचे।

विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माना जाए। प्रकृति का संरक्षण कोई वैकल्पिक विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की शर्त है। यदि खेजड़ी बचेगी तो थार बचेगा, यदि थार बचेगा तो यहां की संस्कृति, कृषि, पशुधन और जैव विविधता बचेगी, और यदि यह सब बचेगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। यही विश्व पर्यावरण दिवस का वास्तविक संदेश और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

लेखक पर्यावरण संघर्ष समिति, थार मरुस्थल के संयोजक हैं

विश्व पर्यावरण दिवस-2026

पवन कुमार गुजर

हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करने का एक वैश्विक अभियान है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और प्लास्टिक कचरे जैसी चुनौतियों के बीच इस दिवस का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। आज यह दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणीय अभियानों में से एक बन चुका है, जिसमें 150 से अधिक देशों के लोग भाग लेते हैं। हर साल एक नई थीम और मेजबान देश के साथ यह दिवस मनाया जाता है, ताकि किसी विशेष पर्यावरणीय समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया जा सके।

साल 2026 में भी विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ मनाया जा रहा है। इस बार का फोकस प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर है, जो समुद्रों, नदियों, वन्यजीवों और मानव स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर रही है। 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कदम उठाना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस को मेजबानी अजरबैजान देश कर रहा है। अजरबैजान के बाकु शहर में मुख्य वैश्विक समारोह है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष दिवस मनाने का निर्णय लिया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। तब से यह दिन हर साल किसी विशेष पर्यावरणीय विषय के साथ मनाया जाता है। यह लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। सरकारों और समाज को सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाने का संदेश देता है।

राजस्थान में बाल सुरक्षा की अनूठी पहल 'उमंग': एक मानवीय संकल्प

नफीस आफरीदी

राजस्थान में बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें शोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा 'विशेष अभियान उमंग' आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक पहल के रूप में सामने आया है। यह अभियान केवल सरकारी कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि उस मानवीय सोच का विस्तार है जो यह मानती है कि हर बच्चे को भय, भूख, मजदूरी और हिंसा से मुक्त होकर शिक्षा, खेल, सपनों और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित इस अभियान का सातवाँ चरण उमंग-7 वर्ष 2026 में पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बालश्रम, बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी, भीख मंगवाने वाले गिरोहों और बच्चों के विभिन्न प्रकार के शोषण पर प्रभावी रोक लगाना है। आज जब आधुनिकता और विकास की बातें बड़े स्तर पर की जा रही हैं, उसी समय समाज का एक बड़ा और पीड़ित वर्ग ऐसा भी है जहाँ अनेक बच्चे अपनी भी कारखानों, ढाबों, ईट-भट्टों, दुकानों, खानों और घरेलू कामों में अपना बचपन खो रहे हैं। ऐसे समय में 'उमंग' जैसे अभियान संवेदनशील समाज की आवश्यकता बन जाते हैं।

भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू किया जाए। राजस्थान में यह अभियान इसी सोच के साथ प्रारंभ किया गया कि बच्चों को केवल अपराध या गरीबी का हिस्सा मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित जीवन की ओर वापस लाना भी राज्य और समाज की जिम्मेदारी है। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में विशेष टीमें गठित की गई हैं जो उन स्थानों पर लगातार छापेमारी और निरीक्षण कर रही हैं जहाँ बच्चों से मजदूरी कराए जाने या उनके शोषण की आशंका रहती है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फैक्ट्रियाँ, मोटर गैरेज, ईट-भट्टे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाले बाजार और औद्योगिक क्षेत्र इस अभियान के प्रमुख केंद्र हैं। इन स्थानों से अनेक बच्चों को मुक्त कराया जा रहा है और उन्हें बाल कल्याण समितियों तथा पुनर्वास संस्थाओं के माध्यम से सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा रहा है। विशेष अभियान उमंग को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। सामान्यतः ऐसे अभियानों में बच्चों को छुड़ाने के बाद प्रक्रिया समाप्त हो



जाती है, लेकिन उमंग में पुनर्वास को भी उतना ही महत्व दिया गया है। बचाए गए बच्चों को अस्थायी आश्रय, भोजन, चिकित्सा और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। कई बच्चों को उनके परिवारों से पुनर्मिलन कराया जाता है, जबकि जिन बच्चों के परिवार सुरक्षित नहीं होते उन्हें संरक्षण गृहों और शैक्षणिक संस्थाओं से जोड़ा जाता है। यह प्रयास इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि पुनर्वास की व्यवस्था मजबूत न हो तो बच्चे पुनः शोषण के उसी चक्र में लौट जाते हैं जिससे उन्हें मुक्त कराया गया था। इस दृष्टि से उमंग केवल पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण का अभियान भी है।

राजस्थान जैसे बड़े राज्य में बालश्रम और बाल तस्करी की समस्या अनेक सामाजिक और आर्थिक कारणों से जुड़ी हुई है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की कमी कई परिवारों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देती है जहाँ बच्चे ही परिवार की आय का साधन बन जाते हैं। कुछ मामलों में बच्चों को बेहतर रोजगार या शिक्षा का झौंसा देकर दूसरे राज्यों या शहरों में ले जाया जाता है और फिर उनसे अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जाता है। कई बच्चे भीख मंगवाने वाले संगठित गिरोहों के चंगुल में फँस जाते हैं।

यह स्थिति केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय संकट भी है। उमंग अभियान इन पारंपरिक बालश्रमों को ध्यान में रखते हुए पुलिस, प्रशासन, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक संगठनों के समन्वय से चलाया जा रहा है ताकि बच्चों की सुरक्षा बहुआयामी रूप में सुनिश्चित की जा सके।

इस अभियान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष समाज में जागरूकता फैलाना भी है। अक्सर लोग होटलों, दुकानों या घरों में काम करते छोटे बच्चों को देखकर भी सामान्य मान लेते हैं। कई बार बालश्रम को गरीबी की मजबूरी कहकर स्वीकार कर लिया जाता है।

यही सोच सबसे बड़ी समस्या बनती है। उमंग अभियान लोगों को यह संदेश देता है कि बालश्रम केवल सामाजिक बुराई नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। किसी बच्चे के हाथ में किताबों की जगह औजार या बर्तन देना उसके भविष्य को अंधकार में धकेलना है। इसलिए आम नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि यदि वे किसी बच्चे को शोषण या मजदूरी की स्थिति में देखें तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दें। जब समाज जागरूक होगा तभी ऐसे अभियानों की सफलता स्थायी रूप से सुनिश्चित हो सकेगी।

इक्कीसवीं सदी के इस तकनीकी और वैश्विक युग में बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न और अधिक जटिल हो गया है। आज केवल पारंपरिक बालश्रम ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन शोषण, मानव तस्करी के नए तरीके और खतरे बनकर उभर रहे हैं। ऐसे समय में उमंग जैसे अभियान यह भरोसा दिलाते हैं कि राज्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति गंभीर है। राजस्थान पुलिस द्वारा जिला स्तर पर विशेष अधिकारियों की नियुक्ति, निरंतर निगरानी और संयुक्त कार्रवाई यह दर्शाती है कि सरकार इस समस्या को केवल औपचारिकता के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे सामाजिक न्याय के प्रश्न के रूप

में स्वीकार कर रही है। उमंग शब्द स्वयं आशा, उत्साह और नए जीवन का प्रतीक है। यह नाम इस अभियान की आत्मा को व्यक्त करता है। जिन बच्चों ने गरीबी, हिंसा, शोषण और उपेक्षा के बीच अपना बचपन खो दिया, उनके जीवन में फिर से सपनों की रोशनी लौटाना ही इस अभियान का उद्देश्य है। जब कोई बच्चा कारखाने या ढाबे से निकलकर स्कूल की कक्षा में पहुँचता है, जब उसके हाथों से मजदूरी के औजार हटकर किताबें आ जाती हैं, तब केवल एक बच्चा का जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरा समाज अधिक सभ्य और मानवीय बनता है। निष्कर्षतः राजस्थान का विशेष अभियान उमंग बाल सुरक्षा की दिशा में अत्यंत प्रेरणादायक और आवश्यक पहल है। यह अभियान हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति उसकी ऊँची इमारतों, तकनीकी उपलब्धियों या आर्थिक आँकड़ों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहाँ के बच्चे कितने सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं। यदि समाज और प्रशासन मिलकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तो वह दिन दूर नहीं जब हर बच्चे का बचपन सचमुच सुरक्षित और खुशहाल होगा।



मल्टी-सिस्टम इन्फ्लैमेटरी सिंड्रोम नई चिंता, कैसे निपटें

कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने लगी है लेकिन अन्य गंभीर बीमारियां बढ़ते से लेकर बच्चों में पाई जा रही है। बड़ों में अलगा किरम की जीवनघातक बीमारियां हो रही हैं तो दूसरी ओर बच्चों में कोविड के बाद मल्टी-सिस्टम इन्फ्लैमेटरी सिंड्रोम (एमआईएस-सी) बीमारी पाई जा रही है। पिछले साल 2020 के मुकाबले इस साल 2021 में बच्चों में कोविड-19 और एमआईएस-सी के केस लगातार सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है मल्टी-सिस्टम इन्फ्लैमेटरी सिंड्रोम, लक्षण और उपाय।

मल्टी-सिस्टम इन्फ्लैमेटरी सिंड्रोम क्या है ?

यह बीमारी कोविड-19 से ठीक होने के बाद बच्चों में पाई जा रही है या परिवार में कोई संक्रमित हो गया था उनसे भी दूरी बनाकर एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। कोविड-19 से संक्रमित बच्चों के ठीक होने के बाद परिजन को कम से कम 6 से 8 सप्ताह तक बच्चों की अच्छे से देखभाल करना है। क्योंकि यह बीमारी कोविड-19 से ठीक होने के बाद जन्म ले रही है। कोविड-19 से ठीक होने के बाद जब रक्षा प्रणाली शरीर में अति सक्रिय हो जाती है।

जिससे पाचन तंत्र, हृदय, फेफड़े, ब्लड वेसल, दिमाग जैसे अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है और यह सूजने लग जाती है। इस बीमारी के अमेरिका और यूके में अधिक केस सामने आ रहे थे। लेकिन अब भारत में भी इसका प्रभाव बढ़ता दिख रहा है।

मल्टी-सिस्टम इन्फ्लैमेटरी सिंड्रोम के लक्षण

तेज बुखार, पेट दर्द, हाई, फेफड़ों में समस्या होना, मस्तिष्क प्रभावित होना। इसी के साथ शरीर पर लाल चकते होना, आंखें लाल होना, जीभ लाल पड़ना। यह बीमारी एकदम पकड़ में नहीं आती है।

मल्टी-सिस्टम इन्फ्लैमेटरी सिंड्रोम से बचाव के उपाय

यूरोप के नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक इस बीमारी के बलाए गए लक्षण दिखने पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इस बीमारी से ठीक होने के लिए इंटावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी और एस्पिरिन दो तरह की दवा दी जाती है। डॉक्टर लक्षण के मुताबिक कॉर्टिकोस्टेरोयड्स भी देते हैं। लेकिन सभी अलग-अलग लक्षण के अनुसार दी जाती है।

मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए जरूर अपनाएं ये घरेलू उपाय



पुरुषों के मुकाबले यह समस्या ज्यादातर महिलाओं में अधिक होती है। इसका मुख्य कारण उनके हारमोन्स में अधिक उतार-चढ़ाव आना है। यह छाले अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। इनके निकलने के कई कारण हो सकते हैं। पेट के साफ न होने और खाना खाते समय अचानक दांतों से मुंह के अंदर की झिल्ली के कट जाने से छाले हो जाते हैं। मासिक

धर्म या मेनापॉज के सामय हारमोन्स में बदलाव तथा वायरस, बैक्टीरिया या फंगस संक्रमण से निकल सकते हैं। इसके अन्य कारणों में शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम होना, एलर्जी होना भोजन में विटामिन सी और बी12 की कमी होना आदि शामिल हैं। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में भी मुंह में छाले निकल सकते हैं।

छालों से बचाव के उपाय

खाना धीरे-धीरे चबा-चबा कर खाएं। खाते समय बात न करें, ताकि दांतों से मुंह के अंदर की परत को नुकसान न पहुंचे।

- नींबू को आधा काटें, इसे छाले पर लगाएं, इससे थोड़ी जलन तो होगी, परंतु यह सुन्न हो जाएगा, जो अच्छा है। आखिर में थोड़ा शहद छाले पर लगाएं।
- शरीर की सफाई, संतुलित भोजन और पीने के साफ पानी पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है।
- कुछ दिनों तक लगातार विटामिन सी और विटामिन बी12 की गोलियां खाएं।
- माउथवाश का प्रयोग करें- कई बार कुल्ला करने से यह आपके मुख में बढ़ने वाले जीवाणुओं को साफ करता है और इसके साथ-साथ कई मामलों में छाले में दर्द से राहत देता है। किसी बिना नुस्खा घोल का उपयोग करें, कोई भी माउथवाश इस प्रयोजन के लिए कार्यकारी है। सुबह और शाम कुल्ला करें और हो सके तो दिन के खाने के बाद भी कुल्ला करें।

हलवा देता है पौष्टिक फायदे

- सूजी का हलवा बना रहे हैं तो सूजी के दाने थोड़े मोटे ही लें, एकदम बारीक नहीं। यह पाचन तंत्र के लिए बेहतर होता है।
- अगर आटे का हलवा बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि आटा जरा मोटा पिसा हुआ हो, ये चिपकेगा नहीं और स्वाद व पाचन दोनों के लिए अच्छा रहेगा।
- अगर नुकसान से बचना चाहते हैं, तो डालडा या बाजार के घी के बजाए देसी घी या गाय के शुद्ध घी का प्रयोग



- करें। देशी घी में बना हलवा त्रिदोषों का संतुलन करता है।
- हलवे को सूर्योदय के पहले उठकर मुंह धोकर पकाते हुए तुरंत गर्मी-गरम खाना चाहिए।
- हलवा टंडा करके न खाएं, इसे गर्मागर्म ही परोसे ताकि सिरदर्द या न्यूरो वेस्कुलर डिसऑर्डर जैसी समस्याओं में फायदा मिल सके।
- हलवा खाने के तुरंत या कुछ देर बाद तक भी टंडा पानी न पिएं, वरना आप इसके फायदों को नहीं पा सकेंगे। आधे घंटे बाद ही पानी पिएं।
- हलवा पचने में बहुत हल्का होता है, इसलिए इसे सर्जरी के बाद, प्रसव के बाद, कमजोरी में, बीमारी से उबरने में और कम वजन वाले लोगों को भी दिया जा सकता है।
- हलवे में केसर, इलायची और थोड़े से सूखे मेवों का प्रयोग किया जा सकता है।
- देशी घी में बना हलवा त्रिदोषों का संतुलन करता है और हमें स्वस्थ बनाता है।
- शकर की जगह गुड़ का प्रयोग करेंगे, तो स्वाद और सेहत दोनों के फायदे पा सकेंगे। अगर आपको शकर ही डालना है, तो ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं।

नोट : मधुमेह रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए जरूर अपनाएं ये घरेलू उपाय

आजकल ज्यादातर लोगों में कमर दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है जिसकी चपेट में बड़ी उम्र के लोग ही नहीं, बल्कि युवा के लोग भी आ रहे हैं। कमर दर्द के होने का मुख्य कारण बदलती जीवनशैली के साथ ऑफिस में घंटों गलत पॉश्चर बैठे रहना है। यह समस्या अब न केवल उम्र से जुड़ी है बल्कि इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी तकलीफदेह साबित हो रही है। कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप कई तरह के घरेलू उपचार करते हैं लेकिन इसका प्रभाव मात्र कुछ समय के लिए ही रहता है। आइए आज हम आपको कुछ घरेलू उपायों के बारे में बता रहे हैं जिसे अपनाने से जल्दी ही छुटकारा पा सकती है। कमर दर्दकमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप एक खड़ाई में सरसो का तेल डालकर उसमें लहसुन की तीन-चार कलियों के साथ अजवाइन को डालकर

गर्म कर लें। टंडा होने पर इस तेल से कमर की मालिश करें। इस उपाय से आपको जल्द ही राहत मिलेगी। कढ़ाई में दो-तीन चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब इस गर्म नमक को किसी सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। और इस पोटली से कमर की सिकाई करें काफी जल्द ही आराम मिलने लगेगा। ऑफिस में काम करते समय ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना। हर चालीस मिनट में अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ी देर टहल लें। कैल्शियम की कम मात्रा से भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जो कमर के दर्द का प्रमुख कारण बनती है इसलिए कैल्शियमयुक्त चीजों को सेवन करें। अजवाइन को तवे पर डालकर धीमी आंच पर सेंके और टंडा होने पर धीरे-धीरे चबाते हुए निगल जाएं। इसके नियमित सेवन से कमर दर्द में लाभ मिलता है।



ग्रीन टी से ज्यादा लाभकारी है नीली चाय

ग्रीन टी और ब्लैक टी के बारे में तो आप जानते ही हैं, और इनका सेवन भी करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी ब्लू टी यानि नीली चाय पी है आपने? अगर नहीं पी है तो एक बार जरूर ट्राय कीजिए, क्योंकि सेहत और ब्यूटी के लिए बेहद फायदेमंद है ये नीली चाय

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चाय नीली कैसे होती है, तो हम आपको बता दें कि ये चाय अपराजिता के खूबसूरत नीले फूलों को उबालकर बनाई जाती है, इसलिए इसका रंग नीला होता है। इसे बटरफ्लाई टी भी कहा जाता है। जानिए इसे बनाने की विधि और 5 गजब के फायदे -
विधि - इस चाय को बनाने के लिए आपको चाहिए, अपराजिता के नीले फूल, पानी और स्वाद अनुसार नमक, शकर या नींबू। सबसे पहले पानी उबाल लें और उसमें अपराजिता के फूल डालें। जब इसका रंग नीला हो जाए, तो इसमें नमक या शकर डालें और कुछ बूंद नींबू की डालकर छान लें। अब यह पीने के लिए तैयार है। अब जानिए इसके फायदे -

डिटॉक्स टी

आपके शरीर से अवांछित तत्वों को बाहर निकालकर ये चाय बॉडी को डिटॉक्स करती है और शरीर की आंतरिक सफाई करती है।

इम्युनिटी बूस्टर

यह एक बेहतरीन इम्युनिटी बूस्टर की तरह काम करती है और इम्युनिटी को बढ़ाकर बीमारियों से आपकी रक्षा करती है।

डायबिटीज

यह नीली चाय डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह शुगर के लेवल को मेंटेन करने में काफी मददगार होती है।

ब्यूटी बेनिफिट्स

खूबसूरती को और निखारना चाहते हैं तो नीली चाय एक बढ़िया विकल्प है। यह चेहरे के दाग, धब्बे और झाइयों को मिटाकर रंगत निखारने में सहायक है।

माइग्रेन

माइग्रेन के मरीजों के लिए सुबह इस चाय का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। यह दर्द के अलावा दिमागी थकान को भी दूर करती है।



कोरोना वैक्सीन से पहले और बाद में बिल्कुल न करें ये काम

18 से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। युवाओं में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसका उन्हें वैक्सीनेशन के दौरान ध्यान रखना जरूरी है। लापरवाही बरतने पर यह बातें मारी भी पड़ सकती है। वैक्सीनेशन के कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। ध्यान नहीं देने पर वैक्सीनेशन का असर विपरीत भी पड़ सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें।

शराब का सेवन न करें

वैक्सीनेशन से पहले भूलकर भी शराब का सेवन नहीं करें। इससे वैक्सीन का प्रभाव कम हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन से पूर्व आप खूब सारा पानी पिएं और पेट भरकर खाना खा कर जाएं।

दर्द निवारक दवा नहीं लें

वैक्सीन लगवाने के पूर्व किसी भी प्रकार की दर्द निवारक दवा नहीं लें। अगर आपको मामूली सा दर्द है तो घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। कुछ दवा वैक्सीन के प्रति विपरीत रिप्लैट भी कर सकती है। इसलिए वैक्सीनेशन के 24 घंटे पूर्व कोई पेन किलर नहीं लें, बाद में भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें।

यात्रा करने से बचें

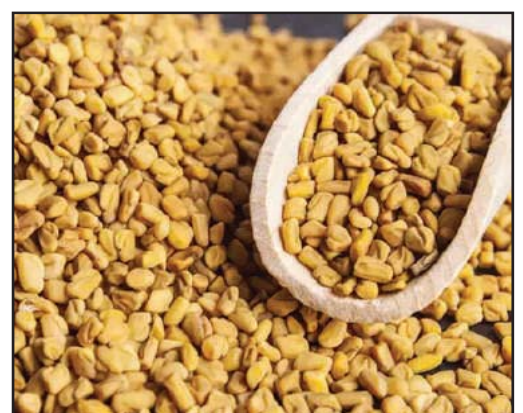
वैक्सीनेशन के बाद बैफिक होकर बिल्कुल भी नहीं घूमें। यह भ्रम नहीं पाले कि वैक्सीनेशन हो गया है तो अब हमें कोरोना नहीं होगा। बल्कि वैक्सीनेशन के बाद आप किसी भी तरह की यात्रा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है।

मैथीदाने का प्रयोग आप खाने के स्वाद को बढ़ाने में करते हैं, लेकिन इसके सेहत और सौंदर्य लाभ आपको हैरत में डाल देंगे। आइए जानते हैं इनके अनमोल गुण।

- मैथीदाने का चूर्ण प्रतिदिन खाने से आपका वजन नियंत्रित रहता है और वसा की मात्रा धीरे-धीरे कम हो जाती है। इस तरह से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं।
- मैथीदाने का नियमित सेवन दिल की बीमारियों को भी दूर रखने में भी मदद करता है। यह दिल का दौरा पड़ने की आशंका को बेहद कम कर देता है और आप अपने हृदय को रख सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ।
- मधुमेह के मरीजों के लिए मैथीदाना बहुत फायदेमंद होता है। इसको रोज रात में भिगोकर रखने के बाद रोज सुबह चबाकर खाने से और इसके पानी के सेवन से लाभ मिलता है।
- बालों की खूबसूरती के लिए भी मैथीदाना फायदेमंद है। इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से बालों से रूखापन गायब होता है, साथ ही बाल मजबूत बनते हैं।
- चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने में भी यह

मैथीदाना के 5 फायदे आपको पता होना चाहिए

मैथीदाना कुछ कम गुणवान नहीं है। इसे पीसकर चेहरे पर लगाने से त्वचा में चमक के साथ कसाव आता है। इसके अलावा रूखी त्वचा वालों के लिए यह बहुत लाभप्रद है, क्योंकि यह त्वचा को नमी प्रदान करता है।



बीजेपी पृष्ठभूमि से कांग्रेस के 'फायरब्रांड' तक: विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़ विपक्ष की सबसे दमदार आवाज बने 'खाचरियावास'

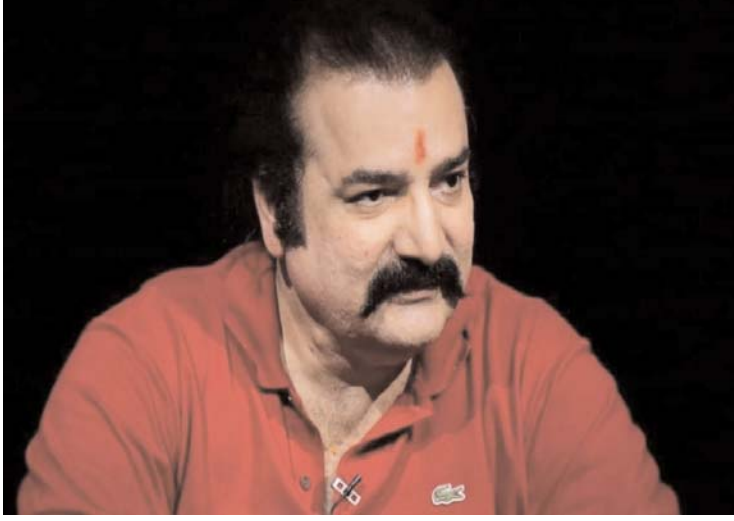
छात्र राजनीति से कैबिनेट मंत्री तक संघर्ष और बेबाकी से बनाई प्रतापसिंह ने अपनी अलग पहचान

एबीवीपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय जीता चुनाव

पूर्व मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत के भतीजे ने खुद लिखी अपनी सियासी इबारत

नीरज मेहरा। जयपुर

कहने को तो वे देश के पूर्व उप राष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री 'बाबोसा' भैरोसिंह शेखावत के भतीजे हैं, लेकिन राजनीति की बिसात पर उन्होंने कभी विरासत का सहारा नहीं लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से कदम बढ़ाकर सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने तक का सफर कभी आसान नहीं था। भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि से



निकलकर कांग्रेस के 'फायरब्रांड' और विपक्ष की सबसे दमदार आवाज बनने की यह कहानी कड़ी मेहनत, जनता के जुड़ाव और कभी न झुकने वाले तेवरों की गवाह है। जो हां, आज की इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास।

जब करियर की शुरुआत में ही विरोधियों ने घेरा-

प्रतापसिंह का सियासी सफर साल 1992 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष बनने से शुरू हुआ था। भाजपा पृष्ठभूमि होने के बावजूद जब अखिल भारतीय विद्यार्थी

कांग्रेस में बनाई जगह, बने संकटमोचक -

साल 2004 के आसपास प्रतापसिंह खाचरियावास ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन धाम लिया। विचारधारा पूरी तरह अलग थी, लेकिन अपनी आक्रामक शैली और जमीनी पकड़ के चलते उन्होंने बहुत जल्द कांग्रेस आलाकमान का भरोसा जीत लिया। साल 2008 में कांग्रेस ने उन्हें जयपुर की हॉट सीट 'सिविल लाइंस' से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। हालांकि 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2018 में वे फिर से इसी सीट से विधायक चुने गए और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में परिवहन तथा खाद्य एवं नगरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और हर मोर्चे पर पार्टी के लिए मजबूती से खड़े रहे।

सड़कों के संघर्ष से बने विपक्ष की 'फायरब्रांड' आवाज -

खाचरियावास की सबसे बड़ी यूएसपी उनका जनता के बीच रहना और जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतर जाना है। चाहे अपनी ही सरकार के खिलाफ बेबाकी से बोलना हो या केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ डटकर खड़े होना, वे हमेशा मुखर रहे हैं। आज भले ही सूबे की सत्ता बदल चुकी है, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक वे कांग्रेस और विपक्ष की सबसे मजबूत तथा धारदार आवाज बनकर सरकार को घेर रहे हैं। उनका यह सफर इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो सियासत की राह में आने वाले हर कठिने को जनसमर्थन के बल पर हटाया जा सकता है।

परिषद ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया, तो इस युवा नेता ने हार नहीं मानी। उन्होंने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और एकतरफा जीत हासिल कर अपने दमखम का परिचय दिया।

इसके बाद वे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन अपनों के ही राजनीतिक छलावे और टिकट न मिलने के कारण विरोधियों ने शुरुआत में ही उनका करिअर कुचलने की पूरी कोशिश की।

चिकित्सा मंत्री के बेटे को जान से मारने की धमकी: फोन कर कहा- जयपुर आओ तो ध्यान रखना; गोली मार दूंगा

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले ने गोली मारने की बात कही है। धनंजय सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। धनंजय की रिपोर्ट पर शनिवार को खींवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जयपुर आओ तो ध्यान रखना, गोली मार दूंगा

खींवर थानाधिकारी अदिति उपाध्याय ने बताया- चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवर के बेटे धनंजय सिंह ने खींवर थाना पुलिस को शनिवार को रिपोर्ट दी। जिसमें उन्होंने कहा- 5 जून को सुबह करीब साढ़े 8 से साढ़े 9 बजे के बीच मैं अपने खींवर फोर्ट स्थित निजी कार्यालय 'अटल भवन' में बैठा था। इसी दौरान मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया, जिसमें नंबर दिखाई नहीं दे रहा था, अनजान लिखकर आ रहा था।

फेसबुक पेज पर भी मिल रहे धमकी भरे मैसेज

रिपोर्ट में धनंजय सिंह ने बताया कि फोन के अलावा मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कुछ समय से लगातार इसी तरह के धमकी भरे मैसेज और कमेंट मिल रहे हैं। इन धमकियों के स्क्रीनशॉट और यूआरएल भी पुलिस को सबूत के रूप में सौंपे हैं। धमकियों के इस सिलसिले से परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

जयपुर में मिशन हरियालो राजस्थान को गति: 66 लाख पौधारोपण का लक्ष्य, जियोटैगिंग से होगी पूर्ण पारदर्शिता

कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में जयपुर अग्रणी: लक्ष्य 125 के मुकाबले 741 रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण

जयपुर।

मिशन हरियालो राजस्थान की जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं राज-उन्नति की 6वीं बैठक में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा जिला कलक्टर संदेश नायक ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में की।

जिला कलक्टर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने, राजस्थान में कृषि वानिकी को विकसित करने, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने तथा भारतवर्ष में 2070 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचाने में राजस्थान प्रदेश की अग्रिम भूमिका को देखते हुए राजस्थान को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में मिशन 'हरियालो राजस्थान' की महत्ता को देखते हुए इसके व्यापक क्रियान्वयन हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले को 66 लाख 82 हजार 538 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है जिसमें से 45.64 लाख पौधे जिले की विभिन्न नर्सरियों में तैयार की गई हैं। शेष पौधों की व्यवस्था निजी स्तर पर की जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि पौधारोपण कार्य हेतु संबंधित विभागों द्वारा लक्ष्यानुसार गहड़े खोदने के कार्य



किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पौधारोपण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप के माध्यम से जियोटैगिंग की जायेगी। उन्होंने बताया कि साथ ही गत वर्ष में किए गए पौधारोपण की रि-जियो टैगिंग कर जीवितता भी अपडेट की जाएगी।

कर्मभूमि से मातृभूमि

जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान जैसे मरुप्रदेश जहाँ आदिकाल से पानी की कमी रही है वहाँ जल संरक्षण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान भूजल विभाग द्वारा 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान का संचालन वर्षाजल की एक-एक बूंद का संरक्षण, संवर्धन व जल पुनर्भरण संरचनाओं का जनसहभागिता से निर्माण कर राज्य में गिरते भूजल स्तर

को रोकने के साथ-साथ आमजन को जागरूक कर व्यवहार परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 125 संरचनाओं के लक्ष्य के विरुद्ध 254 रिचार्ज स्ट्रक्चरों का निर्माण किया जा चुका है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 125 संरचनाओं के विरुद्ध 741 रिचार्ज स्ट्रक्चरों का निर्माण आज दिनांक तक किया जा चुका है। जिला कलक्टर ने रीको सहित सभी विभागों को अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन हेतु संरचनाओं का निर्माण करने हेतु निर्देशित किया है।

इस दौरान जिला कलक्टर ने सीएमओ, जनसुनवाई व संपर्क पोर्टल पर दर्ज जिले से संबंधित सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से पूर्ण

संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश सभी उपखण्ड अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

इस दौरान सीईओ जिला परिषद् प्रतिभा वर्मा, उपवन संरक्षक वी केतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय व जिला जनगणना अधिकारी देवयानी, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय मेघराज मीणा, नॉडल अधिकारी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान भूजल विभाग डॉ. मलेन्द्र चौहान सहित संबंधित विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस में ओपीडी सेवाओं का किया औचक निरीक्षण

ओपीडी में चिकित्सा व्यवस्था, मेडिसिन सहित साफ-सफाई की ली जानकारी

अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार के लिए निर्देश, विभाग की ओपीडी में ही जांच और दवा काउंटर की व्यवस्था हो सुनिश्चित

जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर ओपीडी सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की ओपीडी में चिकित्सा व्यवस्थाओं, दवाओं, जांच सहित साफ-सफाई के संबंध में अस्पताल प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली। साथ ही, उन्होंने रोगियों एवं उनके परिजनों से आत्मीयता से बातचीत की तथा उनसे मिले फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भीवावाड़ा दौरे से जयपुर वापसी पर अचानक एसएसएस अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने धनंजय भवन में ओपीडी सेवाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिसिन, ऑर्थो, कार्डियो, न्यूरो सहित अन्य विभागों की ओपीडी सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल देश का प्रतिष्ठित अस्पताल है। यहां प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के रोगी भी उपचार के लिए आते हैं, जिसके चलते



रोगी भार अधिक रहता है। इसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन सेवाओं में विस्तार और तकनीकी उपाय अपनाकर रोगियों को सुगम एवं सुलभ उपचार उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि रोगियों को जांच और दवाओं के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़े, इसके लिए संबंधित विभाग की ओपीडी में ही जांच और दवा काउंटर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं, उन्होंने अस्पताल परिसर में रोगियों और उनके परिजनों के लिए बैठने एवं पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ ही साफ-सफाई रखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य

सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बना रही है, जिससे यहां मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। विगत ढाई वर्षों में एसएसएस में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। इसके लिए चिकित्सा विभाग एवं अस्पताल प्रशासन साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जहां भी सुधार की गुंजाइश है, वहां जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, एसएसएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. मृगाल जोशी सहित चिकित्सक एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

बाधिन-रिद्धि तीसरी बार मां बनी, एक शावक को दिया जन्म

अब 77 टाइगर हुए, इससे पहले साल 2023 में तीन शावकों को जन्म दिया था

सवाई माधोपुर

रणथंभोर में बाधिन टी-124 रिद्धि ने तीसरी बार एक शावक को जन्म दिया है। जिससे वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। बाधिन को हाल ही में

नाल घाटी वन क्षेत्र में एक शावक के साथ देखा गया है। इससे पहले साल 2022 में एक शावक फिर साल 2023 में तीन शावकों को जन्म दिया था। वन विभाग की लगातार गश्त और निगरानी के दौरान बाधिन और उसके शावक की उपस्थिति दर्ज की गई है। रणथंभोर टाइगर रिजर्व में बाघ, बाधिन और शावकों की संख्या 77 हो गई।

रणथंभोर टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 23 बाधिन 25 बाघ 29 शावक हैं। वन विभाग कर रहा निगरानी रणथंभोर टाइगर रिजर्व फर्स्ट के डीएफओ मानस सिंह ने बताया- इस बाधिन रिद्धि एवं उसके शावक का निगरानी पर वन विभाग लगातार निगरानी रख रहा है, ताकि उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

बारां पुलिस का नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार : 1.46 करोड़ रुपये की 732 ग्राम स्मैक बरामद

जयपुर। कोटा रेंज में चलाए जा रहे विशेष मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत बारां पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाणिज्यिक मात्रा में 732 ग्राम स्मैक बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्वल स्मैक की कीमत लगभग 1 करोड़ 46 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा तस्करों में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज के निर्देशन में 23 मई से 20 जून तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. कमल कुमार के सुपरविजन तथा वृत्ताधिकारी ताराचंद के नेतृत्व में थाना छीपाबड़ौद पुलिस ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। गश्त के दौरान थानाधिकारी छीपाबड़ौद योगेश चौहान मय टीम को आखाखेड़ी चौगहे के पास दो सड़िथ मोटरसाइकिलों के साथ तीन व्यक्ति

खड़े दिखाई दिए। पुलिस जासे को वहीं में देखकर तीनों व्यक्ति घबराकर भागने लगे। इसी कारण वे अपनी सक्रियता साबित करने के लिए लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत अपने ही सहयोगियों पर हमला बोल रहे हैं और बार-बार पुराने विवादों को उठाकर कांग्रेस के भीतर के मुद्दों को सार्वजनिक कर रहे हैं। यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन गहलोत जिस प्रकार लगातार बयान दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर कहा कि 26

छीपाबड़ौद क्षेत्र के ही निवासी हैं। तलाशी के दौरान आरोपी रवि मिश्र और विमल प्रकाश के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा की 732 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। इस ज्वल की गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 46 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और एमओबी टीम बारां में प्रारंभिक जांच में बरामद पदार्थ में मॉर्फिन की मात्रा होने की पुष्टि की है।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार के आगमन से पार्टी को मिलेगी नई मजबूती अशोक गहलोत का राजनीतिक वजूद लगातार घटता जा रहा है, इसी के चलते कर रहे हैं अनर्गल बयानबाजी: मदन राठौड़

जयपुर

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में अजेय कुमार की नियुक्ति भाजपा संगठन के लिए अत्यंत खुशी और गर्व का विषय है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन की भावना का सम्मान करते हुए अनुभवी एवं समर्पित कार्यकर्ता अजेय कुमार को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। शनिवार को जयपुर आगमन पर संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिले के संगठनात्मक प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चा के अध्यक्ष-महामंत्री, बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान की टोली, अभियान के प्रकल्पों की मानिट्रिंग टीम उपस्थित रही।



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने अपना संपूर्ण जीवन समाज और संगठन की सेवा को समर्पित किया है तथा उनके अनुभव का लाभ राजस्थान भाजपा को मिलेगा। उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त, सक्षम एवं प्रभावी बनेगा तथा नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि संगठन महामंत्री की नियुक्ति के बाद अब उन्हें प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच अधिक समय देने का अवसर मिलेगा। भाजपा का मूल आधार संगठन है और संगठन महामंत्री की सक्रिय भूमिका से पार्टी की संगठनात्मक शक्ति और मजबूत होगी। राठौड़ ने कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा पहले से तैयार है और अब संगठनात्मक दृष्टि से और अधिक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन महामंत्री अजेय कुमार संगठन को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाएंगे तथा भाजपा सभी चुनावों में सफलता प्राप्त करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता यह समझ चुकी है कि अशोक गहलोत का राजनीतिक प्रभाव लगातार कम हो रहा है, उनका राजनीतिक वजूद घटता जा रहा है। इसी कारण वे अपनी सक्रियता साबित करने के लिए लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत अपने ही सहयोगियों पर हमला बोल रहे हैं और बार-बार पुराने विवादों को उठाकर कांग्रेस के भीतर के मुद्दों को सार्वजनिक कर रहे हैं। यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन गहलोत जिस प्रकार लगातार बयान दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर कहा कि 26

मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और अब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के बयानों से स्पष्ट है कि अशोक गहलोत की अर्थव्यवस्था को गहलोत ने घटाया है और उसका प्रयास रहेगा कि जनता की अपेक्षाओं पर और अधिक खरा उतरे। राठौड़ ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार जनसेवा के लिए समर्पित है। भाजपा विकास और सेवा के इस अभियान को और गति देगी तथा जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का कार्य करेगी।